समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Sunday, 20 September 2026

दिल्ली सरकार ट्रैफिक जुर्माना चुकाने के लिए एक मौका और छूट भी देगी, जाने डिटेल्स

Sanket Morankar Published on 15 Sep 2025

दिल्ली में लाखों वाहन चालकों के लंबित ट्रैफिक चालान अब जल्द ही निपट सकते हैं। दिल्ली सरकार ने एक नई योजना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत लोगों को उनके बकाया चालानों को चुकाने के लिए **वन-टाइम रीबेट स्कीम (One Time Rebate Scheme)** का विकल्प दिया जाएगा। यह योजना उन वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है, जो वर्षों से ट्रैफिक फाइन की वजह से परेशान हैं।

❓ क्यों आई इस योजना की जरूरत?

दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी में करोड़ों रुपये के ट्रैफिक चालान अभी भी लंबित हैं।

- ई-चालान प्रणाली लागू होने के बाद से ही बड़ी संख्या में लोग जुर्माना नहीं भर पाए हैं।
- अदालतों में भी ऐसे मामलों का बोझ बढ़ गया है।
- न तो वाहन मालिक समय पर चालान भरते हैं और न ही अदालतों के पास इन्हें निपटाने का पर्याप्त समय होता है।

ऐसे में सरकार को एक **व्यवहारिक समाधान** निकालने की जरूरत महसूस हुई, जिससे लोगों को राहत भी मिले और सरकार का राजस्व भी सुरक्षित हो।

❓ क्या होगी योजना की खासियत?

सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्तावित योजना के तहत:

- चालान धारकों को **छूट के साथ अपने लंबित चालान निपटाने का मौका** मिलेगा।
- यह एक **सीमित समय अवधि की योजना** होगी, जिसमें केवल तय समय तक ही रीबेट का लाभ मिलेगा।

- योजना में बड़े जुर्माने (High Penalty) वाले चालानों पर भी आंशिक राहत दी जा सकती है।

⍰ किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?

यह योजना खासकर उन वाहन चालकों के लिए लाभकारी होगी:

- जिन पर **एक से ज्यादा चालान लंबित** हैं।
- जिनके चालान अदालत में फंसे हुए हैं।
- जिन्होंने लंबे समय तक फाइन भरने की हिम्मत नहीं की क्योंकि चालान की रकम बहुत ज्यादा हो गई थी।

⍰ सरकार का नजरिया

दिल्ली सरकार का मानना है कि यह योजना:

- लोगों को राहत देने के साथ-साथ **सरकारी खजाने की आय बढ़ाने** में मदद करेगी।
- अदालतों और ट्रैफिक विभाग पर चालान निपटाने का बोझ घटेगा।
- सड़कों पर नियमों का पालन करने की जागरूकता भी बढ़ेगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, *“[illegible]”*

⍰ क्या कह रहे हैं लोग?

- वाहन मालिकों का कहना है कि यह योजना लंबे समय से जरूरी थी क्योंकि ई-चालानों के कारण कई बार लोग अनजाने में भी फंस जाते हैं।
- ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने भी इसका स्वागत किया है और कहा है कि छोटे वाहन चालकों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।

⍰ आगे की राह

फिलहाल यह प्रस्तावित योजना कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रही है। उम्मीद है कि दिल्ली सरकार इसे जल्द ही लागू करेगी। योजना के लागू होने के बाद लोगों को एक **निर्धारित पोर्टल या मोबाइल ऐप** के जरिए अपने चालान चेक करने और रीबेट स्कीम का लाभ उठाने का मौका मिलेगा।

दिल्ली सरकार की यह पहल लाखों वाहन चालकों के लिए राहत भरी साबित हो सकती है। जहां एक ओर लोग चालानों के बोझ से मुक्त होंगे, वहीं सरकार को भी राजस्व की वसूली आसान होगी। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि योजना को कितनी सफलता मिलती है और लोग किस हद तक इसका लाभ उठाते हैं।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.